Volume 1, Issue 2, October-December 2026
e-ISSN: 2839-5247

Journal of INDIAN KNOWLEDGE STUDIES (JIKS)

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और अंतर-राज्यीय संबंध एकीकरण की चुनौतियाँ और सार्क की भूमिका

[1]*शिखा प्रजापति, [2]प्रवीण कुमार सिंह

[1]शोध छात्रा राजनीति विज्ञान श्री गणेश राय पी० जी० कॉलेज, डोभी जौनपुर

[2]विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान श्री गणेश राय पी० जी० कॉलेज, डोभी जौनपुर

[*]shikhaprajapati645@gmail.com

सारांश

दक्षिण एशिया भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। यह शोध-पत्र दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की बाधाओं का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के संदर्भ में। पत्र की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि क्या दक्षिण एशिया को पूर्ण अर्थों में क्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के लिए साझा हित, आर्थिक पूरकता और सहयोग की सामूहिक इच्छा आवश्यक होती है। इसके बाद संघर्ष समाधान, प्रवासन शासन और आपदा जोखिम प्रबंधन में सार्क की भूमिका पर हुए हालिया अध्ययनों की समीक्षा की गई है। पत्र औपनिवेशिक विरासत, भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता, श्रीलंका का तमिल प्रश्न, जातीय और धार्मिक समानताएँ तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर सहित अंतर-राज्यीय संबंधों का विश्लेषण करता है। साथ ही आर्थिक सहयोग का आकलन करते हुए दिखाया गया है कि प्रतिस्पर्धी निर्यात संरचना, कमज़ोर परिवहन संपर्क, तकनीकी कमियाँ और गैर-शुल्क बाधाएँ व्यापार को सीमित करती हैं, तथा भारत का आकार और उसका व्यापार अधिशेष छोटे पड़ोसियों में आशंका पैदा करता है। पत्र का तर्क है कि राजनीतिक अविश्वास बार-बार एकीकरण के लाभों पर भारी पड़ा है, इसलिए सार्क अपने संस्थापक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है।

मुख्य शब्द

दक्षिण एशिया, सार्क, क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण, भारत-पाकिस्तान संबंध, अंतर-राज्यीय संबंध।

ARTICLE HISTORY
Received: 15 September 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 15 October 2026
Published: 23 October 2026

CITATION
शिखा प्रजापति., (2026). दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और अंतर-राज्यीय संबंध एकीकरण की चुनौतियाँ और सार्क की भूमिका. *Journal of Indian Knowledge Studies (J. Indian Knowl. Stud.)*, 1(2), 48-53.
https://doi.org/10.71371/jiks.48-53

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया के इतिहास का परिचय देते समय "विविधता में एकता" का उल्लेख सामान्य बात है, किंतु इसे "एकता में विविधता" कहना अधिक उपयुक्त होगा। विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं और चारों ओर से घिरे समुद्रों ने इस उपमहाद्वीप को अलग पहचान दी है। फिर भी, इन सीमाओं के भीतर प्राकृतिक विविधता अत्यंत व्यापक है: ऊँचे पर्वत, हरित मैदान, शुष्क मरुस्थल और पठारी क्षेत्र। इस विविध भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने एक साझा सांस्कृतिक वातावरण विकसित किया है, परंतु साथ ही अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को भी बनाए रखा है। हजारों वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों ने बाहरी दुनिया के साथ सांस्कृतिक

आदान-प्रदान किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संतुलन स्थापित किया।

मूलतः किसी क्षेत्र को कुछ विशिष्ट मानकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जब कुछ देश भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के निकट हों और उनके बीच साझा राष्ट्रीय हित हों, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक शामिल हैं, तो उन्हें एक 'क्षेत्र' कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन देशों में यह समझ भी होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की बजाय सहयोग को प्राथमिकता देना आवश्यक है। साथ ही, एक स्थायी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र बनाने की सामूहिक इच्छा भी होनी चाहिए।

दक्षिण एशिया में इन भावनाओं का अभाव देखा गया है, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) के वर्षों के कम प्रभावी प्रदर्शन से स्पष्ट होता है। 1985 में सार्क की स्थापना के बाद भी इस क्षेत्र में सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम कार्य किया गया है।

दक्षिण एशिया में सहयोग की कमी के पीछे यह तथ्य है कि यह क्षेत्र अभी भी 'क्षेत्र' के रूप में विकसित हो रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं: पहला, सदस्य देशों के बीच हितों की पर्याप्त पूरकता का अभाव; और दूसरा, आंतरिक संघर्षों और संकटों में लगातार उलझे रहने के कारण देशों के पास क्षेत्रीय समाधान के लिए समय और संसाधनों की कमी।

2 साहित्य की समीक्षा

बिन्यामिन, मुहम्मद एवं अन्य (2025): दक्षिण एशिया आज भी विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जो आर्थिक रूप से विविध और भू-राजनीतिक रूप से जटिल है। इस क्षेत्र में निरंतर सुरक्षा चुनौतियाँ और आर्थिक असमानताएँ भी मौजूद हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके बावजूद राजनीतिक चुनौतियों, क्षेत्रीय विवादों और ऐतिहासिक संघर्षों के कारण सार्क अपने मूल उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने में असफल रहा है। यह अध्ययन आर्थिक एकीकरण को संघर्ष समाधान के साधन के रूप में उपयोग करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने में सार्क की भूमिका का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत संगठन के कूटनीतिक संवाद और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया है; साथ ही यह भी देखा गया है कि अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता, सीमापार आतंकवाद और सैन्य टकराव क्षेत्रीय स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन सार्क की उन सीमाओं का भी आकलन करता है जो संघर्ष को कम करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि संरचनात्मक कमियाँ, प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक असमानताएँ। यह शोध दर्शाता है कि व्यापार समझौतों, सुरक्षा सहयोग पहलों और संपर्क के माध्यम से आर्थिक परस्पर निर्भरता शांति के निर्माण में योगदान दे सकती है। नीति ढाँचों और आर्थिक रणनीतियों का विश्लेषण करते हुए यह अध्ययन यह रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि सार्क किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर सकता है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि सार्क को दक्षिण एशिया में प्रभावी संघर्ष समाधान संस्था के रूप में कार्य करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक एकीकरण दोनों की आवश्यकता है।

उल्लाह, अस्म (2025): दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक प्रवासन प्रवाह वाले क्षेत्रों में से हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के प्रबंधन में जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यह अध्याय श्रम प्रवासन, पर्यावरणीय और राजनीतिक संकटों के कारण होने वाले विस्थापन तथा अनियमित प्रवासन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करता है। इसमें यह भी अध्ययन किया गया है कि सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने प्रवासन शासन को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीतियों के बीच किस प्रकार का संबंध विकसित हुआ है। अध्याय में संभावित सहयोग के आधार पर प्रवासन शासन ढाँचे को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। यह अध्ययन इस विविध क्षेत्र में प्रवासन से जुड़ी जटिलताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए व्यापक नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है; साथ ही मानवाधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है।

रविंदर एवं डॉ. सोनिका (2023): दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस सार में आपदा जोखिम प्रबंधन में सार्क की भूमिका का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है,

जिसमें संगठन के प्रमुख कार्यों और उसके प्रभाव पर विशेष ध्यान और भूस्खलन जैसी अनेक प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने, जीवन बचाने और क्षेत्र की जनसंख्या के कल्याण की रक्षा करने के उद्देश्य से सार्क सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। यह दक्षिण एशिया में आपदा प्रतिरोधक क्षमता और प्रबंधन में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

कासिम, मुहम्मद आदि (2023): दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण अभी भी एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है। इस लेख में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के महत्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सार्क सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा सहयोग को समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। इस अध्ययन में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का विश्लेषण किया गया है तथा उन मूल कारणों की पहचान की गई है जिनसे समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। साथ ही सार्क की भूमिका का भी अध्ययन किया गया है और यह प्रश्न उठाया गया है कि क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सार्क की गति क्यों धीमी है। अध्ययन ने क्षेत्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी उजागर किया है तथा उन संभावनाओं और लाभों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो क्षेत्र के विकास को दिशा दे सकते हैं। लेख में यह तर्क दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सकारात्मक राजनीतिक और आर्थिक संबंध पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंत में, अध्ययन ने सार्क देशों के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से वे आपसी द्विपक्षीय समस्याओं का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और आर्थिक सहयोग को मजबूत बना सकते हैं।

3 दक्षिण एशिया में अंतर-राज्यीय संबंध

दक्षिण एशिया को विश्व के "महत्वपूर्ण क्षेत्रों" या "सुरक्षा परिसरों" में से एक माना जाता है, मुख्यतः इस कारण कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देश विभिन्न स्तरों पर अंतर-राज्यीय विवादों और संघर्षों में उलझे हुए हैं। यद्यपि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने दक्षिण एशियाई देशों को एक साझा औपनिवेशिक ढाँचे के अंतर्गत ला दिया, उसी के साथ उसने कई प्रकार के मतभेदों के बीज भी बो दिए, जो आज तक इस क्षेत्र के अंतर-राज्यीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दो-राष्ट्र सिद्धांत को लेकर मतभेद तथा श्रीलंका और भारत के बीच तमिल बागान श्रमिकों की राष्ट्रीयता का प्रश्न इस संदर्भ में दो प्रमुख उदाहरण हैं। ब्रिटिश राज के अंतिम चरण में जल्दबाजी में हुए प्रस्थान और दो प्रमुख दक्षिण एशियाई देशों के शासक वर्गों के बीच उत्पन्न कटुता ने पारंपरिक सहयोग और एकता को गंभीर रूप से बाधित किया। वास्तव में, यह ऐतिहासिक तथ्य कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एकीकृत भारत के अलग हुए हिस्से हैं, पूरे क्षेत्र को एक विशिष्ट जटिलता प्रदान करता है। जातीय और भाषाई जटिलताएँ इस स्थिति को और भी कठिन बना देती हैं।

दक्षिण एशियाई देशों में फैले विभाजित समुदायों से उत्पन्न समस्याएँ विशेष रूप से जटिल हैं, विशेषकर जब खुली सीमाएँ इन देशों की जनता के बीच निरंतर संपर्क को प्रोत्साहित करती हैं। यह संपर्क अक्सर राज्यों के बीच अविश्वास का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में मुसलमानों की हत्या पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। भारत-श्रीलंका संबंध भी श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभाव और कभी-कभी दुर्व्यवहार के कारण तनावपूर्ण बने रहते हैं। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के टूटने और भारतीय शांति सेना की वापसी के बाद भी दोनों देशों के संबंधों में विशेष सुधार नहीं हुआ है। एलटीटीई संकट को लेकर दोनों देश एक-दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि रखते हैं, जबकि श्रीलंका तमिल टाइगर्स की बढ़ती हिंसा से अकेले जूझ रहा है, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है।

दक्षिण एशिया में भाषाओं और धर्मों का ओवरलैप भी अंतर-राज्यीय संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा जातीय तनावों का चुनावी लाभ के लिए उपयोग एक स्थायी खतरा बना हुआ है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएँ, जैसे लोकतंत्र, सैन्य शासन और राजतंत्र, मौजूद हैं। यद्यपि अधिकांश देशों का औपनिवेशिक अतीत और सामाजिक मूल्य समान हैं, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भिन्नताएँ मौजूद हैं। भारत और श्रीलंका अपेक्षाकृत सफल लोकतंत्र माने जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र अभी पूरी तरह संस्थागत नहीं हो पाया है। नेपाल में भी लोकतंत्र अभी स्थिर नहीं है। भूटान में राजशाही का प्रभाव है और मालदीव में

बहुदलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हुआ है।

शासन के मूल्यों और सिद्धांतों में भी अंतर दिखाई देता है। भारत का राजनीतिक ढाँचा लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का मिश्रण रहा है। बांग्लादेश ने भी प्रारंभ में ऐसे ही सिद्धांत अपनाए, लेकिन बाद में धार्मिक प्रभाव बढ़ा। पाकिस्तान की राजनीति इस्लाम पर आधारित है, जबकि मालदीव भी एक इस्लामी समाज है। नेपाल पर हिंदू प्रभाव है और भूटान तथा श्रीलंका बौद्ध समाज हैं। इस प्रकार, दक्षिण एशिया में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएँ और शक्ति संरचनाएँ देखने को मिलती हैं।

4 दक्षिण एशिया आर्थिक सहयोग

दक्षिण एशिया में विद्वानों का एक व्यापक नेटवर्क होने के बावजूद, अकादमिक अनुशासन नीति-निर्माण या कार्रवाई-उन्मुख नहीं हैं। इसलिए चुनौती यह है कि ये विद्वान नेटवर्क आपसी सहयोग के माध्यम से नए संघर्षों पर विचार-विमर्श के मंच तैयार करें और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़कर निवारक उपायों को प्राथमिकता दें। आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों का भी दृढ़ता से समाधान करना आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान को अपने परमाणु कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभावों का भी सामना करना होगा।

यदि भविष्य में भारत-पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है, विशेषकर परमाणु हथियारों के साथ, तो इसके गंभीर और अकल्पनीय परिणाम होंगे: भारी जनहानि, पर्यावरणीय परिवर्तन, जैविक उत्परिवर्तन और सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता।

दक्षिण एशिया में एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि छोटे देश अपने बड़े पड़ोसी से भयभीत रहते हैं, विशेषकर जब द्विपक्षीय संबंधों में जटिलताएँ हों। इस संदर्भ में भारत को अक्सर 'बड़े भाई' के रूप में देखा जाता है और पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ उसके विवाद अधिक तीव्र हैं।

अन्य छह देश सार्क को एक ऐसे मंच के रूप में देखते हैं जहाँ वे भारत के प्रभाव का सामूहिक रूप से सामना कर सकें। 1993-94 में भारत का सभी सदस्य देशों के साथ व्यापार अधिशेष था, और व्यापार उदारीकरण इस असंतुलन को और बढ़ा सकता है।

भारत और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार स्तर कम है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ संसाधनों, उत्पादन संरचना और सेवाओं की आपूर्ति में एक-दूसरे की पूरक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, भारत और नेपाल जूट उत्पादों में प्रतिस्पर्धा करते हैं; भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश चाय के निर्यात में प्रतिस्पर्धा करते हैं; और भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश वस्त्र निर्यात में अमेरिका और यूरोप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार, जटिल राजनीतिक, आर्थिक और संरचनात्मक कारक दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को सीमित करते हैं।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण एशिया को एक पूर्ण विकसित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के बीच शांति और स्थिरता की इच्छा की अपेक्षा संघर्ष की प्रवृत्ति हमेशा अधिक प्रभावी रही है। आशा की जाती है कि ऐसे रुझानों को उत्साहपूर्वक प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि निकट भविष्य में दक्षिण एशिया को लंबे समय से अभावग्रस्त 'क्षेत्रीयता' की गुणवत्ता प्रदान की जा सके। यह भी आशा की जानी चाहिए कि, चाहे समाधान कितने ही जटिल क्यों न हों, अंततः उन्हें लागू किया जाएगा, ताकि 'दक्षिण एशिया' नामक एक आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और सामाजिक-राजनीतिक रूप से अधिक सुसंगठित क्षेत्र का निर्माण किया जा सके।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का क्षेत्र भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता से संपन्न है, फिर भी यह विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। सदस्य देशों के सामाजिक-विकास, अवसंरचनात्मक और आर्थिक संकेतकों की भी तुलना की जाती है। सार्क देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता के अस्तित्व के कारणों पर चर्चा की गई है, चाहे वह समूह में भारत की स्पष्ट प्रभुत्वशाली स्थिति हो, जो अन्य सदस्यों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है, या सदस्य देशों के बीच राजनीतिक गतिरोध।

यद्यपि अधिक आर्थिक एकीकरण और व्यापार से होने वाले लाभों की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, फिर भी मूलभूत परिवहन संपर्क की कमी, तकनीकी समन्वय का अभाव तथा गैर-शुल्क बाधाएँ व्यापार लागत को बढ़ाती हैं और वैध व्यापार में बाधा उत्पन्न करती हैं। बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना सभी देशों द्वारा सर्वसम्मति से एक पूर्व-आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है; तथापि, उनके राजनीतिक मतभेदों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने से उन्हें अब तक दूर रखा है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया को अभी पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। इन देशों में भूगोल, इतिहास और संस्कृति की समानता है, किंतु क्षेत्रीय सहयोग के लिए आवश्यक पर्याप्त साझा हितों और सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। औपनिवेशिक विरासत, विभाजन और उसके बाद के अनसुलझे विवादों, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच, ने संबंधों को संदेह से भरा रखा है। सीमाओं के आर-पार फैली जातीय और भाषाई समानताएँ तथा लोकतंत्र, राजतंत्र और सैन्य शासन जैसी भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएँ तनाव को और बढ़ाती हैं। परिणामस्वरूप, शांति और स्थिरता की इच्छा की तुलना में संघर्ष की प्रवृत्ति अधिक प्रबल रही है, और सार्क विवादों के समाधान का प्रभावी तंत्र नहीं बन सका।

आर्थिक विश्लेषण भी इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करता है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक कम और प्रतिस्पर्धी अधिक हैं, जैसे जूट, चाय और वस्त्र निर्यात में। इसलिए क्षेत्र के भीतर व्यापार का स्तर कम है, और कमज़ोर परिवहन संपर्क, तकनीकी कमियाँ तथा गैर-शुल्क बाधाएँ व्यापार लागत बढ़ाती हैं। भारत की प्रमुख स्थिति और अन्य सदस्यों के साथ उसके व्यापार अधिशेष के कारण छोटे देशों को आशंका रहती है कि उदारीकरण से असंतुलन और बढ़ेगा, और कई देश सार्क को मुख्यतः भारत के प्रभाव को संतुलित करने के मंच के रूप में देखते हैं। बेहतर संपर्क व्यापार की पूर्व-शर्त है, फिर भी राजनीतिक मतभेदों के कारण इस साझा समझ पर अमल नहीं हो पाया है।

फिर भी, आर्थिक एकीकरण और व्यापार से मिलने वाले संभावित लाभ बहुत बड़े हैं, और आपदा प्रबंधन तथा प्रवासन शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग दिखाता है कि जहाँ राजनीति अनुमति दे, वहाँ संगठन उपयोगी हो सकता है। इसलिए यह पत्र निष्कर्ष देता है कि सार्क को प्रभावी क्षेत्रीय संस्था बनने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और गहन आर्थिक एकीकरण दोनों की आवश्यकता है। संपर्क सुविधाओं में सुधार, व्यापार बाधाओं में कमी, द्विपक्षीय विवादों के प्रबंधन के तंत्र का निर्माण, तथा निवारक कूटनीति में शैक्षणिक नेटवर्क और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना व्यावहारिक कदम हैं। यदि इन पर अमल किया जाए, तो दक्षिण एशिया समय के साथ वह क्षेत्र बन सकता है जिसकी गुणवत्ता उसमें अब तक नहीं रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अनवर, अनु (2019), "दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भागीदारी: अमेरिका के लिए चुनौतियाँ", पैसिफिक फोरम, इश्यूज एंड इनसाइट्स कार्य-पत्र, खंड 19, कार्य-पत्र 6, जून 2019, पृष्ठ 1-12।
2. आचार्य, नीलांबर (2019), "नेपाल: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विकल्प नहीं हो सकती", टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 जून 2019।
3. आमिर, लतीफ और अहमद, आदिल (2022), "ताशकंद घोषणा ने भारत और पाकिस्तान को आगे के विनाश से बचाया", अनादोलु एजेंसी, 09.01.2022।
4. उल्लाह, अस्म (2025), "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संगठनों और प्रवासन शासन की जटिलताएँ: दक्षेस सदस्य देशों का अध्ययन"।
5. ओबिनो, फ्रांसेस्को (2009), "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन: दक्षिण एशिया और उससे आगे की राजनीतिक चुनौती", आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 44, अंक 9, पृष्ठ 118-125।
6. कटोच, ध्रुव (2013), "सीमा-पार आतंकवाद से निपटना: एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता", क्लॉज जर्नल, शीतकाल 2013।
7. कन्नन, साईकिरण (2021), "विशेष: श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह का पुनरुद्धार हिंद महासागर में चीन की स्थिति को मजबूत कर सकता है", इंडिया टुडे, 19 मार्च 2021।
8. कासिम, मुहम्मद; आजम, समरा एवं दुर्रानी, मोअज्जम (2023), "दक्षिण एशिया: सबसे कम एकीकृत क्षेत्र: कारण और अवसर"।
9. जगलुल, हैदर (2001), "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का संकट", सिक्योरिटी डायलॉग, खंड 32, अंक 4, सेज प्रकाशन, दिसंबर 2001, पृष्ठ 423-437।
10. जैन, रोमी (2005), "भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन: एक विश्लेषण", इंडियन जर्नल ऑफ एशियन अफेयर्स, खंड 18, अंक 2, पृष्ठ 55-74।

11. तनेजा, निशा (2004), "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्र में अनौपचारिक व्यापार", आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, पृष्ठ 5367-5371।
12. डोसानी एवं रोवेन (2005), "दक्षिण एशिया में शांति की संभावनाएँ", एशिया प्रशांत अनुसंधान केंद्र का अध्ययन, ओरिएंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, भारत।
13. दास, आर. (2009), "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण: संभावनाएँ और चुनौतियाँ", विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली।
14. पचैरी, सुनीता (2019), "दक्षिण एशिया में संघर्ष: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की क्षेत्रीयता के लिए चुनौतियाँ", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन जियोग्राफी, खंड 5, अंक 1, 2019, पृष्ठ 34-41।
15. बिन्यामिन, मुहम्मद; अकरम, सायरा; इमरान, मुहम्मद एवं अकील, मुहम्मद (2025), "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण: संघर्ष समाधान में दक्षेस की भूमिका", सोशल साइंस रिव्यू आर्काइव्स, खंड 3, पृष्ठ 3509-3519।
16. रविंदर एवं सोनिका, डॉ. (2023), "आपदा जोखिम प्रबंधन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की भूमिका", आयरिश इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, खंड 7, पृष्ठ 10-17।

COPYRIGHT:
© 2026 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/